

वोट चोरी के आरोपों पर कांग्रेस का कैंडल मार्च

शिमला/शैल। वोट चोरी करने के राहुल गांधी के आरोपों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने शिमला में वोट चोर गद्दी छोड़ नारे के साथ शेर ए पंजाब से रिज पर महात्मा गांधी की प्रतिमा तक कैंडल मार्च निकाला और कहा कि देश में चुनाव आयोग और भाजपा का नेक्सस चल रहा है। सत्ता में काबिज होने के लिये भाजपा ने वोटो की चोरी की है और मरे हुये लोगों के भी वोट डाले गये हैं जिसे राहुल गांधी ने तथ्यों के साथ देश के सामने लाया है लेकिन चुनाव आयोग इसको लेकर चुप है।

उप-मुख्यमंत्री मुकेश

अग्निहोत्री ने कहा कि राहुल विधानसभा का विश्लेषण किया और उस विश्लेषण से पूरा देश व संसार हिल गया है। पूरे जगत में यह बात चली गयी है कि किस ढंग से वोटो की चोरी व ढाका इस देश में डाला जा रहा है। सत्ता में बने रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने



गांधी ने कर्नाटक की एक वोटों की चोरी की है अगर वोट

ही चोरी होंगे तो देश के लोग कहां जाएंगे उनके पास क्या रह जाएगा। यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। आज पूरे देश में यह कार्यक्रम हो रहा है और बिहार में अधिकार यात्रा निकाली जा रही है जहां चुनाव होने जा रहे हैं। अगर वोट का अधिकार भी नहीं रहेगा तो यह देश कैसे आगे चलेगा।

इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा प्रतिभा सिंह ने कहा कि भाजपा ने देश में लोकतंत्र को कमजोर कर निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। भाजपा ने कर्नाटक व महाराष्ट्र में वोट चोरी

कर जनमत का अपमान किया। अब बिहार में भी कुछ ऐसा ही खेल खेलने की तैयारी की जा रही है। इलेक्शन कमीशन को राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब देना चाहिए।

वहीं कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है। भाजपा ने वोट चोरी की है और लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया है कांग्रेस इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। राहुल गांधी ने तथ्यों के साथ देश की जनता के सामने भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत को उजागर किया है।

रेल परियोजनाओं के निर्माण में केंद्र सरकार निभाए अपनी जिम्मेदारी: मुकेश अग्निहोत्री

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश के विपक्ष के नेता हिमाचल प्रदेश में चल रही रेल परियोजनाओं को लेकर तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार इन परियोजनाओं के विकास के लिए केंद्र सरकार को हर स्तर पर पूरा सहयोग प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इन परियोजनाओं के निर्माण में अपनी जिम्मेदारी को निभाये।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विपक्ष द्वारा यह आरोप लगाना कि प्रदेश सरकार सहयोग नहीं कर रही, पूरी तरह तथ्यहीन और भ्रमक है। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट है कि हम राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर केंद्र सरकार के साथ मिलकर राज्य के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि

रेल परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक और पर्यटन विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये न केवल राज्य के दूरदराज क्षेत्रों को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने में मदद करेंगी बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से भी अहम हैं। हिमाचल जैसे पहाड़ी व विशेष श्रेणी राज्य के लिए रेल संपर्क, सड़क और हवाई संपर्क की तरह ही महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेल लाइन, चंडीगढ़-बढ़ी रेल लाइन और नंगल-तलवाड़ा रेल लाइन परियोजनाएं समयबद्ध पूर्ण हों। इन परियोजनाओं में राज्य सरकार ने न केवल वित्तीय योगदान दिया है बल्कि भूमि अधिग्रहण, प्रशासनिक स्वीकृतियां और अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने में भी सक्रिय भूमिका निभाई है।

उन्होंने कहा कि भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेल लाइन निर्माण के लिए राज्य सरकार ने अब तक राज्य के हिस्से के रूप में 847 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। इस रेलवे लाइन का कार्य प्रगति पर है तथा 31 दिसम्बर, 2027 तक बिलासपुर तक इस कार्य के पूर्ण होने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेल लाइन की लागत में राज्य सरकार द्वारा पहले ही अपना हिस्सा दिया गया है और शेष राशि समय-समय पर प्रदान की जा रही है।

उन्होंने कहा कि इस परियोजना के क्रियान्वयन में देरी हुई है, इसलिए रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा सूचित परियोजना लागत 6.45 गुणा बढ़कर 6753.42 करोड़ रुपये हो गई है। अब राज्य का हिस्सा बढ़कर 2583.01 करोड़ रुपये हो गया है, जिसमें भूमि

अधिग्रहण लागत 1210.42 करोड़ रुपये शामिल है। इस प्रकार राज्य सरकार को कुल परियोजना लागत का 38.84 प्रतिशत हिस्सा व्यय करना पड़ रहा है।

चंडीगढ़-बढ़ी रेल लाइन परियोजना का कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना को भारत सरकार द्वारा विशेष रेलवे परियोजना घोषित किया गया है। 1540.113 करोड़ रुपये लागत की इस परियोजना की लम्बाई 30.28 किलोमीटर है। इसमें राज्य सरकार की हिस्सेदारी 363.50 करोड़ रुपये बनती है, जिसमें से 223.75 करोड़ रुपये उत्तरी रेलवे को दे दिए गए हैं। इस रेलवे लाइन का कार्य 30 अप्रैल, 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

नंगल-तलवाड़ा रेल लाइन का अधिकांश हिस्सा पूरा हो चुका है और इसे नंगल से दौलतपुर चौक तक यातायात के लिए खोला जा चुका है। इस परियोजना की पूरी

लागत केंद्र सरकार वहन कर रही है, जिसमें प्रदेश सरकार ने भी सहयोगी की भूमिका निभाई है। इस परियोजना की लम्बाई 122.57 किलोमीटर है जिसमें से 60.03 किलोमीटर भूमि हिमाचल प्रदेश में और 62.24 किलोमीटर भूमि पंजाब में स्थित है। इस परियोजना का 59.325 किलोमीटर कार्य पूर्ण हो चुका है।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि रेल परियोजनाएं संपूर्ण राष्ट्र के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये परियोजनाएं सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए केंद्र सरकार का दायित्व है कि वह हिमाचल में रेल परियोजनाओं के निर्माण की पूर्ण लागत वहन करे, ताकि उन्हें समयबद्ध पूर्ण किया जा सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां अन्य राज्यों

राज्यपाल ने ठियोग दिवस पर शुभकामनाएं दीं

शिमला/शैल। ठियोग दिवस के अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने क्षेत्र के लोगों को शुभकामनाएं दीं। ठियोग में आयोजित समारोह में जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने क्षेत्र के गौरवशाली इतिहास, समृद्ध



सांस्कृतिक विरासत और राज्य के विकास में क्षेत्र के लोगों के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि ठियोग प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए प्रसिद्ध है और यहां के लोग मेहनती और साहसी हैं।

राज्यपाल ने स्वच्छ सर्वेक्षण-2025 में 20,000 से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर ठियोग को बधाई दी। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बागवानी और पर्यटन के क्षेत्र में ठियोग

की निरंतर प्रगति की सराहना की और यहां के युवाओं में देशभक्ति और देश सेवा की भावना पर प्रकाश डाला।

प्रजामंडल आंदोलन के सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इस अमृतकाल में प्रत्येक नागरिक को देश के निर्माण में सार्थक योगदान देने की आवश्यकता है। उन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वदेशी अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल के माध्यम से ही भारत ने पाकिस्तान को झुकने पर मजबूर किया और आज दुनिया के देश भारत की ताकत का लोहा मान रहे हैं।

राज्यपाल ने ठियोग के लोगों से नशे के विरुद्ध लड़ाई में भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संकल्प की शक्ति से भी क्षेत्र के लोगों ने स्वच्छता में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया और नशे के खिलाफ लड़ाई में भी एकजुटता से जीत हासिल की जा सकती है।

इस अवसर पर राज्यपाल ने श्याम द्वारा लिखित नशे के प्रति

जागरूकता पर आधारित गीत भी लान्च किया। उन्होंने समाज में उत्कृष्ट योगदान के लिए विशिष्ट जनों को भी सम्मानित किया।

इससे पहले, विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने राज्यपाल का स्वागत किया और प्रजामंडल आंदोलन को याद करते हुए कहा कि इस आंदोलन ने शासक को सत्ता जनता को सौंपने के लिए मजबूर किया था। इसके परिणामस्वरूप ठियोग दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई। उन्होंने क्षेत्र में विभिन्न विकासवात्मक पहलों पर भी प्रकाश डाला और राज्यपाल के नशा विरोधी अभियान की सराहना की।

नगर परिषद ठियोग के अध्यक्ष अनिल गोवर ने समारोह के ऐतिहासिक महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला तथा उपाध्यक्ष नीतू मेहता ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। स्थानीय कलाकारों द्वारा चोलटू नृत्य और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए।

इस अवसर पर राज्य वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची, अतिरिक्त उपायुक्त दिव्यांशु, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतन नेगी, उपमण्डलाधिकारी ठियोग शशांक गुप्ता और अन्य गणमान्य भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने केलंग जनजातीय महोत्सव का शुभारम्भ किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद सिंह सुक्खू ने शिमला से चर्चुअल माध्यम द्वारा लाहौल-स्पीति जिला के केलंग में जनजातीय महोत्सव का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को इस महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह महोत्सव पर्यावरण संरक्षण की दिशा में दूरगामी भूमिका निभाएगा। प्रदेश में पहली बार किसी महोत्सव का आयोजन 'जीरो वेस्ट' थीम के साथ किया गया है। इस आयोजन के दौरान पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत अनेक नवोन्मेषी पहल की गई हैं। उन्होंने कहा कि लाहौल-स्पीति जिला की कला एवं संस्कृति विशिष्ट एवं अनूठी है। इस महोत्सव के माध्यम से आने वाले पर्यटकों को क्षेत्र के बारे में और अधिक जानने व समझने का अवसर प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय महोत्सव हमारी विरासत संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। हिमाचल के

पहले 'जीरो वेस्ट' जनजातीय महोत्सव के रूप में यह आयोजन पूरे प्रदेश में लोगों को जिम्मेदारी से उत्सव मनाने के लिए प्रेरित करेगा।

उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण देश व प्रदेश को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लाहौल-स्पीति जिला भी इससे अछूता नहीं है। यहां भी सामान्य से अधिक बारिश होना चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा के दौरान लोगों को राहत प्रदान करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है।

पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने व जलवायु परिवर्तन से निपटने के दृष्टिगत राज्य सरकार, केन्द्र सरकार से मिलकर दृढ़ता से कार्य कर रही है। प्रदेश में केन्द्र के सहयोग से वैज्ञानिकों की टीम बादल फटने की घटनाओं के बारे में गहन अध्ययन कर रही है।

मुख्यमंत्री ने उदयपुर उपमंडल में

पीएमजीएसवाई चरण-3 के तहत 36,41,78,000 रुपये की लागत के पांच पुलों का शिलान्यास किया। इनमें 9 करोड़ 93 लाख रुपये की निर्मित होने वाला चौखंग नाले पर 35 मीटर का सिंगल स्पैन स्टील ट्रस पुल, चिनाब नदी पर 9 करोड़ 46 लाख रुपये से निर्मित होने वाला 49 मीटर सिंगल स्पैन डबल लेन स्टील ट्रस पुल, किशोरी नाले पर 17.68 करोड़ रुपये से निर्मित होने वाला 22 मीटर सिंगल स्पैन आरसीसी-टी बीम पुल, तेलिंग नाले पर 13.35 करोड़ रुपये से निर्मित होने वाला 76 मीटर सिंगल स्पैन आरसीसी बीम पुल और मोरिंग नाले पर 1.89 करोड़ रुपये से निर्मित होने वाला 22 मीटर सिंगल स्पैन आरसीसी बीम ब्रिज शामिल हैं।

विधायक अनुराधा राणा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उन्हें महोत्सव की विस्तृत जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने भूटान सरकार को 5000 से अधिक चिलगोजा के पौधे भेंट किए

शिमला/शैल। रॉयल भूटानी एम्बेसी के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन ताशी पेलडन और मंत्री सलाहकार चिमी



वांगमो के नेतृत्व में भूटान साम्राज्य के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद सिंह सुक्खू से भेंट की तथा परस्पर संबंधों पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और भूटान के बीच संबंध हमेशा सौहार्दपूर्ण रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच 1949 में मैत्री समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसे 2007 में नवीनीकृत किया

गया। उन्होंने कहा कि इन संबंधों को और अधिक मजबूत करते हुए प्रदेश की जनता की ओर से मित्रता के

प्रतीक के रूप में भूटान सरकार के वन एवं पार्क सेवा विभाग को आज 5000 से अधिक चिलगोजा पौधे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी अक्टूबर में, जाईका परियोजना के तहत स्वयं सहायता समूहों द्वारा एकत्र किए गए 50 किलोग्राम चिलगोजा के बीज भी भूटान को प्रदान किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि चिलगोजा

के पौधे जिला किन्नौर तथा जिला चंबा के पांगी और भरमौर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि चिलगोजा के बीज किन्नौर जिला के लोगों की आजीविका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और बाजार में इन्हें अच्छा मूल्य प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि इन बीजों में औषधीय गुणों के साथ-साथ एंटीऑक्सीडेंट तत्व भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उन्होंने भूटान सरकार को चिलगोजा के पौधे लगाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने की पेशकश की।

ताशी पेलडन ने चिलगोजा के पौधे प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक: जे.पी. भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

राज्यपाल ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की श्रद्धांजलि अर्पित की

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला के ऐतिहासिक रिज पर भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की उनकी

आधारित मार्ग पर चलकर हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। राज्यपाल ने कहा कि वाजपेयी जी भारतीय राजनीति में एक महान



पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की।

राज्यपाल ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि वह एक दूरदर्शी राजनेता थे जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में सर्वोच्च नैतिक मूल्यों को बनाए रखा। उन्होंने कहा कि वह हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते थे।

उन्होंने कहा कि उनके द्वारा दिखाए गए सत्य, निष्ठा और मूल्य

व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, जिनकी सभी दिलों द्वारा प्रशंसा की जाती थी और उनकी सादगी, वाकपटुता और कौशल के लिए पूरा देश उन्हें प्यार करता है।

इस अवसर पर उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी दिवंगत नेता को पुष्पांजलि अर्पित की।

कलाकारों द्वारा इस अवसर पर देशभक्ति गीत एवं भजन भी प्रस्तुत किए गए।

मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद सिंह सुक्खू ने शिमला के रिज मैदान पर भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री

जाते थे। कुल्लू जिले के प्राणी में उनका घर है और हिमाचल प्रदेश से उनका विशेष लगाव था।



अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का सभी सम्मान करते हैं और वह एक प्रखर और सच्चे राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने कहा कि वह अपने विचारों की स्पष्टता के लिए जाने

इस अवसर पर विधायक हरीश जनारथा, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान, शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान, उप-महापौर उमा कौशल, नगर निगम के पार्षदगण, उपायुक्त अनुपम कश्यप और अन्य गणमान्य भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने सतीश कुमार को वीर चक्र सम्मान प्राप्त करने पर बधाई दी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद सिंह सुक्खू ने जिला मंडी के जोगिंद्रनगर उप-मंडल के ग्राम पंचायत भुहला भडियारा के समोहली गांव के निवासी, IV डोगरा रेजिमेंट के नायब सूबेदार सतीश कुमार को 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान उनकी वीरता के लिए वीर चक्र से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सतीश कुमार ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान

पाकिस्तान की सेना को मुहत्तोज़ जवाब देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनकी बहादुरी ने पूरे राज्य को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को 'वीरभूमि' के रूप में जाना जाता है। राज्य के वीर जवानों को विभिन्न अभियानों में उनकी बहादुरी के लिए कई वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है जो पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों का ऑनलाइन सत्यापन

शिमला/शैल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों का ऑनलाइन माध्यम से सत्यापन (ई-केवाईसी) करने के लिए एक नया मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इस ऐप के माध्यम से विभाग द्वारा सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों के सत्यापन की प्रक्रिया आरम्भ की गई है, ताकि लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन सुचारु रूप से उनके बैंक अथवा डकघर के बचत

खातों में प्रदान की जा सके।

उन्होंने लाभार्थियों से 31 अगस्त, 2025 से पूर्व नजदीकी आंगनवाड़ी केन्द्रों में जाकर सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित अपना सत्यापन (ई-केवाईसी) करवाने का आग्रह किया।

सत्यापन के लिए आवश्यक जानकारी एवं समस्या निवारण के लिए लाभार्थी अपने नजदीकी बाल विकास परियोजना पर्यवेक्षक, तहसील कल्याण अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिम भोग गेहूं का आटा, दलिया और हल्दी उत्पादों को लॉन्च किया

शिमला/शैल। जिला मंडी के सरकाघाट में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिम भोग गेहूं का आटा, हिम भोग दलिया

सार्वजनिक आर्टवर्क के लिये यह पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोक, शास्त्रीय, गजल, भजन और समूहगान विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए



और हिम भोग हल्दी उत्पादों को लॉन्च किया। यह उत्पाद प्राकृतिक रूप से उगाये गये गेहूं और हल्दी से तैयार किए गए हैं ताकि उपभोक्ताओं को रसायन मुक्त उत्पाद उपलब्ध करवाए जा सकें।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश की तीन प्रसिद्ध हस्तियों को 'प्रेरणा स्रोत' पुरस्कार से सम्मानित किया। शिमला के प्रो. हिम चटर्जी को कांगड़ा मिनिअर पेंटिंग को पुनर्जीवित करने और नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान सुरंग में दुनिया के सबसे लंबे

जिला शिमला के डॉ. राम स्वरूप शांडिल को पुरस्कृत किया गया। उन्होंने सोलन स्थित शूलिनी विश्वविद्यालय के चांसलर प्रो. प्रेम कुमार खोसला को वानिकी शिक्षा में उनके अग्रणी योगदान, जिसमें बी.एससी., एम.एससी. और पीएच.डी. कार्यक्रम शुरू करना शामिल है, के लिए सम्मानित किया। 'हिमाचल गौरव' पुरस्कार के तहत धर्मशाला की चंद्ररेखा डडवाल को उल्लेखनीय साहित्यिक योगदान, कुल्लू के सेउबाग की शालिनी वत्स को दृष्टिबाधित, दिव्यांगजनों, महिलाओं

और बच्चों के सशक्तिकरण में उनके योगदान के लिए तथा छोटा शिमला के डॉ. लाल सिंह को सतत आजीविका, जैव विविधता संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा और कृषि नवाचार पर 50 से अधिक परियोजनाओं का नेतृत्व करने के लिए सम्मानित किया गया।

ग्रामीण विकास विभाग के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी कुल्लू को राज्य स्तरीय सिविल सेवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सरकाघाट और धर्मपुर क्षेत्र के पांच लाभार्थियों को मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के अंतर्गत विवाह अनुदान के रूप में 2-2 लाख रुपये और सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के 11 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के अंतर्गत गृह निर्माण के लिए प्रथम किस्त के रूप में 1.5-1.5 लाख रुपये प्रदान किए। शेष 1.5 लाख रुपये आवास की छत का निर्माण कार्य पूरा होने पर प्रदान किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने इस वर्ष मंडी जिला में आई आपदा के दौरान युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्यों के सफल क्रियान्वयन में बहुमूल्य योगदान देने वाले विभागों, अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ने मंडी, कुल्लू और किन्नौर में भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिला मंडी, कुल्लू और किन्नौर में लगातार भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने प्रभावित जिला के उपायुक्तों से व्यक्तिगत रूप से बात कर क्षति की विस्तृत रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अवरुध सड़कों

की बहाली एवं राहत कार्य में तेजी लाने को भी कहा। उन्होंने लोगों से नदियों और नालों से दूर रहने और समय-समय पर जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस कठिन समय में प्रदेश सरकार पूरे संकल्प के साथ लोगों के साथ खड़ी है।

मुख्यमंत्री से एचडीएफसी बैंक के जूनल हेड ने शिष्टाचार भेंट की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से ओक ओवर में एचडीएफसी बैंक के जूनल हेड विनोद शर्मा ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर बैंक अधिकारियों ने बैंक की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल के तहत ई-एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव दिया।

मुख्यमंत्री ने इस पहल के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत

अनेक अभिनव पहल की है और प्रदेश में ई-वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बैंक की यह पहल न केवल आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के सरकार के दृष्टिकोण में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी।

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर और क्लस्टर हेड शिवेंद्र श्रीवास्तव भी उपस्थित थे।

एचआरटीसी के चालको व परिचालकों को दो करोड़ रुपये की ओटीए-एनओटीए राशि जारी: उप-मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी की चालक यूनियन की हाल ही में हुई बैठक में यूनियन की मांगों पर विचार करते हुए कई अहम निर्णय तत्काल लागू कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने चालकों व परिचालकों को एक माह का ओवर टाईम भत्ता और रात्रि ओवर टाईम भत्तों ओटीए-एनओटीए के लिए दो करोड़ रुपये इस माह जारी कर दिए हैं।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और उनकी समस्याओं का समाधान समयबद्ध सुनिश्चित किया जाएगा।

मुकेश अग्निहोत्री ने पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी और उनकी टीम की सराहना करते हुए कहा कि हाल ही में तीन स्कूली बच्चों के अगवा होने पर 24 घंटे के अंदर अपहरणकर्ता को पकड़कर बच्चों को सुरक्षित उनके परिजनों को सौंप देने का कार्य सराहनीय है।

उद्योग मंत्री ने की बल्क ड्रग पार्क की उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता

शिमला/शैल। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने हिमाचल प्रदेश बल्क ड्रग पार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एचपीबीडीपीआईएल की उच्च स्तरीय समिति की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने समिति की नवीं बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की।

बैठक में कॉमन स्टीम, जिसमें टर्बाइन पावर जनरेशन तथा स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क शामिल हैं, के डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग से जुड़े प्रश्नों पर चर्चा की गई। विभिन्न निविदा कंपनियों ने वर्चुअल माध्यम से तकनीकी सवाल रखे, जिन पर समिति द्वारा विस्तृत चर्चा की गई और बैठक में ही समाधान किया गया। इस निविदा की लागत 300.28 करोड़ रुपये है।

उद्योग मंत्री ने बताया कि इस पार्क का लक्ष्य राज्य में फार्मा उद्योग के लिए विश्वस्तरीय आधारभूत सुविधाएं विकसित करना है, जिससे उत्पादन लागत कम होगी, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा। इसके अतिरिक्त, बल्क ड्रग पार्क के निर्माण से रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने निवेशकों की समस्याओं का समाधान और परियोजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

निदेशक उद्योग एवं बल्क बल्क ड्रग पार्क के लिए गठित राज्य कार्यान्वयन समिति के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. यूनस ने बल्क ड्रग पार्क की प्रगति पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उद्योग विभाग के अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

सरकार ने पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के लिए 3.50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की

शिमला/शैल। राज्य सरकार ने सिरमौर जिला के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में चब्योगा पच्छाद और सलामू राजगढ़ के बीच सड़क मार्ग को मजबूत करने के उद्देश्य से गिरि नदी पर एक पुल के निर्माण के लिए 3.50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी की है। यह जानकारी लोक निर्माण विभाग के प्रवक्ता ने दी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देशों के दृष्टिगत लिया गया है।

प्रवक्ता ने बताया कि इस पुल

के निर्माण से क्षेत्र के विशेषकर करगाणु, राजगढ़, टिककर, पबियाना, द्राबली, वासनी और दाड़ो देवरिया ग्राम पंचायतों के निवासियों को निर्बाध संपर्क सुविधा सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के समग्र एवं संतुलित विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है। सड़कों और पुल प्रगति की रीढ़ हैं और प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क मार्गों को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दे रहे हैं ताकि प्रदेश का कोई भी क्षेत्र सरकार की विकासात्मक योजनाओं से वंचित न रहे।

मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारम्भ किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला के कनलोग क्षेत्र में 76वें राज्य स्तरीय वन



महोत्सव का शुभारम्भ किया। उन्होंने देवदार का पौधा रोपित किया।

मुख्यमंत्री ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का शुभारंभ भी किया। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े मंत्रीगण और विधायकों से संवाद किया तथा वन संरक्षण व

संवर्धन के बारे में विस्तार से चर्चा की।

इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि वन महोत्सव धरती पर जीवन रेखा कहलाए जाने वाले वनों के महत्व को दर्शाता है। इस वर्ष लगभग नौ हजार हेक्टेयर वन भूमि पर विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के अंतर्गत पौधरोपण किया जाएगा, इसमें 60 प्रतिशत फलदार पौधे शामिल होंगे।

प्रदेश सरकार राज्य की समृद्ध जैव-विविधता को और संरक्षित व समृद्ध बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। इससे वर्ष 2030 तक 30 प्रतिशत वन आवरण बढ़ाने के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत वर्ष 2025 से 2030 तक महिला मंडल, युवक मंडल, स्वयं सहायता समूह और संयुक्त वन समितियां एक से पांच हेक्टेयर चयनित वन भूमि पर न केवल पौधे लगाएंगी, बल्कि पांच वर्ष तक उनकी देखभाल

भी करेगी। इसके लिए 100 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष 20 करोड़ रुपये की लागत से 1000 से 1500 हेक्टेयर वन भूमि पर पौधरोपण किया जा रहा है। पौधरोपण व पौधों की देखभाल के लिए एक लाख 20 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर भी प्रदान किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि वन अधिकारी कार्यालय की कार्य प्रणाली के साथ-साथ अपना अधिकांश समय फील्ड में वन विस्तार व संरक्षण को समर्पित करें।

मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत विभिन्न महिला मंडलों को पौधरोपण के लिए एक-एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता के चेक भी भेंट किए। उन्होंने आजीविका वर्धन गतिविधियों के लिए जाईका परियोजना के तहत भी लाभार्थियों को 50-50 हजार रुपये के चेक भेंट किए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. पंत और प्रधान मुख्य अरण्यपाल संजय सूद ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और वन विकास से संबंधित विभिन्न गतिविधियों की विस्तार से जानकारी दी।

अवैध खनन के 895 मामले दर्ज, 44.31 लाख रुपये का लगाया जुर्माना

शिमला/शैल। निदेशक उद्योग डॉ. यूनस ने कहा कि विभाग द्वारा अवैध खनन गतिविधियों पर सख्ती से रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता अवैध खनन की रोकथाम, पारदर्शी खनन को बढ़ावा देना और आमजन में जागरूकता फैलाना है। विभाग ने जिलों में सक्रिय अभियान चलाकर जुलाई, 2025 तक 895 अवैध खनन के मामले दर्ज किए हैं और दोषियों पर कार्रवाई करते हुए लगभग 44.31 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। विभाग ने विशेष अभियान के तहत प्रथम अगस्त से प्रदेशव्यापी विशेष अभियान आरम्भ किया है जिसमें विभागीय टीमों द्वारा खनिज नियमों के अनुपालन की विस्तृत जांच की जा रही है। सभी फील्ड स्टाफ को लगातार अवैध गतिविधियों पर निगरानी रखने और नियमित रिपोर्टिंग करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने खनन अधिकारी से प्राप्त जानकारी को साझा करते हुए कहा कि अब तक अवैध खनन से संबंधित कुल 122 मामले दर्ज किए गए हैं इनमें से 76 मामलों लम्बित हैं जबकि 46 मामलों में कड़ी कार्रवाई करते हुए माइनिंग एक्ट के तहत 3.55 लाख रुपये की जुर्माना राशि वसूली है।

डॉ. यूनस ने कहा कि खनिज संसाधनों का संरक्षण केवल प्रशासनिक दायित्व नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। भौमकीय शाखा में स्थापित शिकायत प्रकोष्ठ को अब तक विभिन्न माध्यमों से कुल 267 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें लैंडलाइन के माध्यम से 95, मोबाइल फोन के माध्यम से 35 और व्हाट्सएप के माध्यम से 137 शिकायतें दर्ज की गई हैं। ईमेल भी एक प्रभावी माध्यम साबित हुआ है जिसके माध्यम से प्रतिदिन औसतन 2 से 3 शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। प्रत्येक जिला के विश्लेषण अनुसार कांगड़ा

से 65, सोलन से 50, बिलासपुर से 23, ऊना से 21 और मंडी से 17 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध खनन को लेकर जन जागरूकता बढ़ रही है और लोग शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खनिज संपदा की लूट को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी व्यक्ति या संस्था अवैध खनन गतिविधियों में सलिप्त पाई जाएगी, उनके विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। डॉ. यूनस ने आम जनता से किसी भी प्रकार की सदिध खनन गतिविधि की जानकारी तुरंत शिकायत प्रकोष्ठ में दर्ज करने और इस अभियान में भागीदार बनने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में व्हाट्सएप नम्बर 08988500249, लैंडलाइन नम्बर 0177-2990575 तथा ईमेल geologicalwing@gmail.com पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

भूल करने में पाप तो है ही, परन्तु उसे छुपाने में उससे भी बड़ा पाप है।महात्मा गांधी

सम्पादकीय

क्या वोट चोरी का आरोप जनआन्दोलन की नयी जमीन होगा



लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की बुनियाद निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव व्यवस्था पर आश्रित है यह एक स्थापित सत्य है। परन्तु जब चुनाव व्यवस्था पर ही वोट चोरी के आरोप लग जायें तो निश्चित रूप से लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। यह खतरा उस समय और बढ़ जाता है जब इस वोट चोरी से सत्ता में आये शासक और इस चुनाव व्यवस्था के संचालन की जिम्मेदारी संभाल रहा संचालन तंत्र इस वोट चोरी के आरोप को मानने से इन्कार कर दे। संसद

में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जिस तरह के आरोप चुनाव आयोग पर लगाये हैं और सत्ता पक्ष की ओर से इन आरोपों का जवाब देने के लिये जिस तरह से पूर्व मंत्री हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर मैदान में उतरे उससे इन वोट चोरी के आरोपों का स्वतः ही सत्यापन हो जाता है। इस समय राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों से जिस तरह का राजनीतिक वातावरण पूरे देश में निर्मित हो गया है उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। ऐसी संभावना बनती जा रही है कि यह मुद्दा एक जन आन्दोलन की शकल लेने जा रहा है।

वैसे तो जब से ईवीएम मशीन के माध्यम से 1998 से वोट डाले जाने लगे हैं तभी से इन मशीनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठते आये हैं। 2009-10 में जब लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब इन मशीनों की व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे थे। भाजपा नेता जी वी एल नरसिम्हा राव ने तब इन आरोपों पर एक पुस्तक तक लिखी थी। आज यह आरोप इन ईवीएम मशीनों से चलकर चुनाव आयोग का संचालन कर रहे तंत्र तक पहुंच गये हैं। भाजपा नीत एनडीए 2014 से केन्द्र की सत्ता पर आसीन है और हर चुनाव में चुनावों की विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहे हैं। लेकिन पहली बार चुनावों में हुई धांधली पर तथ्य परक अध्ययन करके राहुल गांधी सामने आये हैं। स्मरणीय है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने “अबकी बार चार सौ पार” का नारा लगाया था लेकिन यह आंकड़ा दो सौ चालीस पर आकर रुक गया और सरकार बनाने के लिये नीतीश और नायडू का सहारा लेना पड़ा। लोकसभा चुनावों के बाद हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभाओं के चुनाव हुये। इन चुनावों में जिस पैमाने की धांधलियां हुई उसकी पराकाष्ठा तब सामने आयी जब हरियाणा में एक विधानसभा चुनाव का डिजिटल रिकॉर्ड लेने के लिये सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद की यह रिकॉर्ड नहीं मिला और मामला पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय पहुंचा तथा अदालत ने यह रिकॉर्ड देने के आदेश कर दिये। लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश के बाद रात को नियम में संशोधन करके रिकॉर्ड देने से इन्कार कर दिया गया। इससे यह आशंका और बलवती हो गई कि चुनाव आयोग में ऐसा कुछ अवश्य हुआ है जिसे सार्वजनिक होने से रोकने के लिये नियम में ही संशोधन कर दिया गया।

यह स्थितियां बनी जिनसे पूरे अनुसंधान के साथ कर्नाटक की महादेवपुरा सीट का अध्ययन किया गया। इस अनुसंधान के बाद वोट चोरी के पांच रास्ते सामने आये। यह पांच चोर रास्ते इस प्रकार सामने आये (1) डुप्लीकेट वोट (2) फर्जी और अप्रमाणित पते (3) एक छोटे से घर में 80 से अधिक वोट (4) फर्जी फोटो (5) फॉर्म छः का दुरुपयोग। इनके विश्लेषण से सामने आया कि 11965 वोट डुप्लीकेट (2) 10452 वोट एक ही पते पर दर्ज (3) 4509 वोट फर्जी और अप्रमाणित पर दर्ज (4) 4132 वोट अलग फोटो के साथ दर्ज (5) 33692 मामले ऐसे हैं जहां व्यक्ति चार-चार अलग पोलिंग पर दर्ज। आदित्य श्री वास्तव कर्नाटक में दो, उत्तर प्रदेश में एक और महाराष्ट्र में एक पोलिंग बूथ पर दर्ज है और सभी जगह वोट डाले हैं। इण्डिया टुडे की टीम ने अपनी जांच में एक ही पते पर 80 वोट दर्ज होने के आरोप को सही पाया है। इस तरह के आरोप कई लोकसभा क्षेत्रों में सामने आये हैं। इन आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब हास्यस्पद रूप से सामने आया है क्योंकि चुनाव आयोग अपना डाटा सार्वजनिक नहीं कर रहा है। जबकि यह आरोप सीधे अपराध की श्रेणी में आता है और इसके लिये कर्नाटक में मामला दर्ज किया जा सकता है। बिहार में चुनाव आयोग ने जिस तरह से 65 लाख मतदाताओं को सूची से निकाला था उस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सारी स्थिति को बदल दिया। इन वोट चोरी के आरोपों के साथ जिस तरह के सवाल पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और स्व. राज्यपाल सत्यपाल मलिक के प्रति भारत सरकार के आचरण से उभरे हैं उससे यह स्पष्ट हो गया है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता के साथ केन्द्र सरकार की नीयत और नीति पर भी गंभीर सवाल खड़े होते जा रहे हैं। यदि प्रधानमंत्री इन उठते सवालों पर स्वयं जवाब नहीं देते हैं तो परिस्थितियों बहुत जटिल हो जायेंगी।



गौतम चौधरी

तेजी से बदल रही दुनिया में धार्मिक विविधता, हमारे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन गया है। हम देखते हैं कि लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जैसे हिंदू, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन, यहूदी आदि, जिनकी अपनी-अपनी मान्यताएं, परंपराएं और आचार व्यवहार होते हैं। हालांकि ये धर्म ऊपर से अलग दिखते हैं, लेकिन ये अक्सर शांति, प्रेम, दया और दूसरों के प्रति सम्मान जैसे साझा मूल्यों के आधारभूत संरचना पर ही आरुढ़ होते हैं। फिर भी, गलतफहमियों, जानकारी की कमी, विभिन्न प्रकार के पूर्वाग्रह और कभी-कभी राजनीति के कारण धर्म संघर्ष का कारण बन जाता है। ऐसे में अंतर-धार्मिक संवाद का महत्व बढ़ जाता है। यह हमें एक-दूसरे को समझने और शांति से साथ रहने में मदद करता है।

अंतर-धार्मिक संवाद का अर्थ है-अलग-अलग धर्मों के लोगों के बीच खुला और सम्मानजनक संवाद। यह किसी धर्म को श्रेष्ठ साबित करने की बहस नहीं है, बल्कि यह सुनने, समझने और सीखने की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य, आपसी सम्मान बढ़ाना, नफरत कम करना, और ऐसा समाज बनाना जहां हर व्यक्ति सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। यहां यह भी समझना चाहिए कि जब परमात्मा एक है तो उसने जिस किसी को बनाया वह सब उसी की संरचना है। उन संरचनाओं में किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो परमपिता को ही हानि पहुंचती है। इसलिए आपसी संवाद से ही यह तय होगा कि आधिर् ईश्वर और उसके द्वारा रचा गया संचार कितना व्यापक और संवेदनशील है।

धार्मिक मतभेदों के कारण अक्सर अविश्वास, घृणा और हिंसा देखी गई है। हम अक्सर सांप्रदायिक दंगों, सामाजिक तनावों और नफरत फैलाने वाले भाषणों के बारे में सुनते हैं, जो प्रायः अन्य धर्मों के प्रति गलतफहमियों पर आधारित होते हैं। जब व्यक्ति अन्य धर्मों के बारे में नहीं जानते, तो झूठी बातों पर विश्वास करना या नफरत से प्रभावित होना आसान हो जाता है। अंतर-धार्मिक संवाद गलत धारणाओं की दीवारों को तोड़ता

है, समुदायों के बीच मित्रता बनाता है, एक-दूसरे के विश्वास और मूल्यों को समझने में मदद करता है और शिक्षा, पर्यावरण, सामाजिक न्याय जैसे सामान्य लक्ष्यों पर साथ मिलकर काम करने का रास्ता खोलता है। इससे शांति और एकता को बढ़ावा मिलता है और अज्ञान या डर से होने वाली हिंसा को रोका जा सकता है।

अंतर-धार्मिक संवाद का एक बड़ा लाभ यह है कि इससे यह पता चलता है कि सभी धर्मों की शिक्षाओं में कई समानताएं हैं। अधिकतर धर्म शांति और अहिंसा, करुणा और दान, सत्य और ईमानदारी, बुजुर्गों का सम्मान, गरीबों की सेवा, क्षमा और विनम्रता की बात करते हैं। जैसे-हिंदू धर्म ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की बात करता है (सारा संसार एक परिवार है), इस्लाम रहमा (दया) और सलाम (शांति) पर जोर देता है, ईसाई धर्म अपने पड़ोसी से प्रेम करो सिखाता है, बौद्ध धर्म अहिंसा और सचेतनता का समर्थन करता है, सिख धर्म सर्वत दा भला (सबकी भलाई) की बात करता है और जैन धर्म अपरिग्रह (त्याग) और शांतिपूर्ण जीवन पर बल देता है। जब लोग धर्म की सीमाओं से परे बात करते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि वे उतने अलग नहीं हैं जितना उन्होंने सोचा था, या बताया जाता है। यह एक साझा मानवता की भावना को जन्म देता है, जो साम्प्रदायिक सौहार्द की नींव है।

हम विभिन्न धर्मों के बीच संवाद को कई तरीकों से प्रोत्साहित कर सकते हैं। स्कूल और कॉलेजों में छात्रों को सभी धर्मों की जानकारी सम्मानपूर्वक और तथ्यात्मक रूप से दी जानी चाहिए। जब युवा सभी विश्वासों की सुंदरता को समझते हुए बड़े होते हैं, तो वे दूसरों से नफरत नहीं करते। विभिन्न धर्मों के लोगों को साथ लाकर त्योहारों, संगोष्ठियों या कार्यशालाओं का आयोजन समझ को बढ़ाता है। एक-दूसरे के त्योहार मिलकर मनाना खुशी और दोस्ती को बढ़ाता है। मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों आदि के धर्मगुरुओं का समाज पर बड़ा प्रभाव होता है। जब वे एकजुटता की बात करते हैं, तो लोग सुनते हैं। वे अपने अनुयायियों को सहिष्णुता और शांति की राह दिखा सकते हैं। मीडिया नफरत फैलाने के बजाय एकता और सहयोग की कहानियां दिखा सकती है। फिल्में, लेख और सोशल मीडिया एकता और साझा मूल्यों की शक्ति को प्रस्तुत कर सकते हैं। युवा पीढ़ी समाज का भविष्य है। छात्रों और युवाओं के लिए विशेष संवाद सत्र या सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम लंबे समय तक चलने वाले

रिश्ते बना सकते हैं। जब लोग मिलकर सेवा करते हैं, तो वे अपने मतभेद भूल जाते हैं। सेवा का मूल्य सभी धर्म साझा करते हैं।

वर्तमान भारत, भले साम्प्रदायिक चुनौतियों से जूझ रहा हो, फिर भी धार्मिक सौहार्द की कई प्रेरक कहानियां प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए, केरल में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई अक्सर एक-दूसरे के त्योहारों में हिस्सा लेते हैं। पंजाब में मुसलमानों और सिखों ने मिलकर मस्जिदों और गुरुद्वारों की मरम्मत की है। ईद या दीवाली पर विभिन्न समुदायों के लोग मिठाइयां और शुभकामनाएं बांटते हैं। झारखंड के हजारीबाग में रामनौमी का झंडा मुस्लिम कारीगरों के द्वारा बनाया जाता है। ऐसे सांप्रदायिक सदभाव के उदाहरण भरे पड़े हैं। अलग-अलग धर्मों के धर्मगुरु हिंसा रोकने के लिए एक साथ शांति यात्राएं भी निकाल सकते हैं, जिसमें केवल सौहार्द और साम्प्रदायिक सदभाव पर ही चर्चा हो।

अंतर-धार्मिक संवाद को बढ़ावा देना हमेशा आसान नहीं होता। इस क्षेत्र में कई प्रकार की चुनौतियां भी हैं। समाज में अब भी बहुत सी अज्ञानता, पूर्वाग्रह और संदेह मौजूद हैं। राजनीतिक एजेंडा कभी-कभी धर्म का दुरुपयोग कर लोगों को बांटता है। कुछ लोग डरते हैं कि अन्य धर्मों से संवाद करना उनके अपने विश्वास को कमजोर कर देगा। लेकिन संवाद का अर्थ यह नहीं है कि हम हर बात से सहमत हों। यह असहमति के बावजूद एक-दूसरे का सम्मान करना है। सच्चा धर्म खुलापन, नम्रता और करुणा सिखाता है। एक मजबूत विश्वास सीखने से नहीं डरता। इसलिए खुद के विश्वास को कमजोर होने वाली थ्योरी निराधार है।

अंतर-धार्मिक संवाद केवल धर्म का विषय नहीं है-यह एक ऐसे शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण करने की प्रक्रिया है, जहां हर व्यक्ति सम्मानित और सम्मिलित महसूस करे। यह डर और नफरत को मिटाने का एक सशक्त साधन है। जब विभिन्न धर्मों के लोग आपस में बात करते हैं, सुनते हैं और एक-दूसरे से सीखते हैं, तो वे सौहार्द के बीज बोते हैं। ये बीज एकता और शांति के मजबूत वृक्षों में बदलते हैं। भारत जैसे विविधता वाले देश में और एक ऐसे विश्व में जो तेजी से जुड़ता जा रहा है, अंतर-धार्मिक संवाद कोई विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। इसलिए सांप्रदायिक सदभाव के लिए संवाद का सिलसिला प्रारंभ करना यथेष्ट रहेगा।

भारत के आदिवासी समुदाय, जो कि कुल जनसंख्या का 8.6% हैं, राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के मूल तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी, इन समुदायों के कई व्यक्ति जानकारी के अभाव में सिकल सेल नामक अनुवांशिक बीमारी से जूझ रहे हैं। दशकों से इस बीमारी ने उनके स्वास्थ्य के साथ-साथ

राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन

जगत प्रकाश नड्डा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री

ऑफ डिजीज एस्टिमेट्स 2021 रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रति वर्ष अनुमानित 82,500 बच्चों का जन्म सिकल सेल रोग के साथ होता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने इस संकट से निपटने के लिए आधार तैयार किया और इसकी विशिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकताओं पर जोर इसी के आधार पर, केन्द्रीय बजट 2023 में NSCAEM की घोषणा की गई, जिसमें वित्त वर्ष 2025-2026 तक 40 वर्ष से कम आयु के 7 करोड़ व्यक्तियों की मिशन मोड में जांच करने का लक्ष्य रखा गया। कार्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत क्रियान्वित किया गया, जिससे यह विश्व स्तर पर सबसे बड़े जनसंख्या-आधारित आनुवंशिक जांच कार्यक्रमों में से एक बन गया है। इस मिशन का उद्देश्य 2047 तक SCD के आनुवंशिक संचरण को समाप्त करना और पहले से ही इससे पीड़ित लोगों को व्यापक देखभाल प्रदान करना भी है।

पहले दो वर्षों में, स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्यों के संयुक्त प्रयासों से इस मिशन के अंतर्गत उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त हुए हैं। 31 जुलाई 2025 तक,

17 उच्च-व्यापकता वाले राज्यों के 300 से अधिक जिलों में 6.07 करोड़ से अधिक व्यक्तियों की जांच की जा चुकी है। जांच किए गए व्यक्तियों में से 2.16 लाख रोगग्रस्त पाए गए, जबकि 16.92 लाख को वाहक के रूप में पहचाना गया।

विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि 95% मामले केवल पांच राज्यों ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में केंद्रित हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के नवापारा की एक युवा आदिवासी लड़की मीना की कहानी इस मिशन के सकारात्मक प्रभाव का प्रतीक है। जांच अभियान के दौरान नैदानिक परीक्षण किए जाने पर, मीना को निकट के एक उप-स्वास्थ्य केंद्र में नामांकित किया गया। प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ, एएनएम और आशाकार्यकर्ता ने यह सुनिश्चित किया कि उसे निःशुल्क हाइड्रोक्सीयूरिया औषधि समय पर मिलती रहे, जिससे सिकल सेल रोग के लक्षणों में उल्लेखनीय कमी आई। आज, मीना पहले से कहीं अधिक स्वस्थ है और अपने समुदाय में आनुवंशिक रोगों के परामर्श में भी सक्रिय भूमिका निभा रही है।

स्क्रीनिंग प्रयासों में तेज़ी लाने के लिए, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा अनुमोदित पॉइंट-ऑफ-केयर (POC) डायग्नोस्टिक उपकरणों को लगाया गया है। शुरुआत में इनकी संख्या केवल तीन तक सीमित थी, जो अब बढ़कर 30 से अधिक हो गई है। इससे प्रति किट लागत 100 से घटकर 28 हो गई है। इस पहल ने SCD के लिए लागत-प्रभावी और कुशल डायग्नोस्टिक क्षमताएं सुनिश्चित की हैं।

इस मिशन का कार्यान्वयन केवल स्क्रीनिंग पर केंद्रित नहीं है, यह एससीडी से पीड़ित व्यक्तियों की समग्र देखभाल को भी प्राथमिकता देता है। मिशन के अंतर्गत प्रबंधन हस्तक्षेपों में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं, आवश्यक दवाओं और निदान तक पहुंच शामिल है। सिकल सेल रोग के प्रबंधन के लिए एक प्रमुख दवा, हाइड्रोक्सीयूरिया, को राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची ईडीएल में शामिल किया गया है और अब यह आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप-स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है, जिससे अंतिम व्यक्ति तक इसकी पहुंच सुनिश्चित होती है।

यह मिशन सिकल सेल रोग के उन्मूलन की प्रमुख रणनीतियों के रूप में आनुवंशिक परामर्श और जन जागरूकता पर भी जोर देता है। अब तक 2.62 करोड़ से अधिक आनुवंशिक स्टेटस कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को उपयोगी स्वास्थ्य जानकारी प्राप्त हुई है। ये कार्ड परामर्श और उचित निर्णय लेने का एक प्रभावी माध्यम बन गए हैं, जो परिवारों को ऐसे विकल्प चुनने में मदद करते हैं जिनसे आनुवंशिक संचरण का जोखिम कम हो सकता है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और जनजातीय कार्य मंत्रालय से प्राप्त वित्तीय सहायता के आधार पर, पंद्रह स्वास्थ्य परिचर्या संस्थानों/मेडिकल कॉलेजों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए चुना गया है। ये संस्थान प्रसवपूर्व निदान और गंभीर सिकल सेल रोग जटिलताओं के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे जोखिम वाले परिवारों को विशेष परिचर्या सुनिश्चित की जाती

है। इसके अतिरिक्त, अक्टूबर 2024 में आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को सिकल सेल रोग प्रबंधन की जटिलताओं का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान किए गए हैं।

मिशन की सफलता "Whole-of-Government" के दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसके तहत स्वास्थ्य मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भी शामिल किया गया है। यह अंतर-मंत्रालयी समन्वय जनजातीय स्वास्थ्य के सामाजिक-सांस्कृतिक और भौगोलिक आयामों का समाधान करते हुए समग्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा समर्थित अनुसंधान-आधारित गतिविधियों ने इस मिशन की लागत-प्रभावशीलता और रोगी परिणामों में उल्लेखनीय सुधार किया है।

हालांकि इस मिशन की अब तक की उपलब्धियां बेहद सराहनीय हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय अब मिशन की दीर्घकालिक प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। अब मिशन का तात्कालिक ध्यान आनुवंशिक परामर्श, जन जागरूकता अभियानों और आनुवंशिक स्टेटस कार्डों के वितरण के विस्तार पर होगा। सामुदायिक स्तर के मंचों का प्रभावी उपयोग यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होगा कि प्रत्येक वाहक और रोगग्रस्त व्यक्ति को आवश्यक परिचर्या और सहायता प्राप्त हो। उन्नत अनुसंधान प्रयास मिशन की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी एवं सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होंगे।

इस मिशन की असली भावना इसके आदर्श "हमारे संघर्षकर्ताओं को साथ, हमारे उत्तरजीवियों को संबल, और हमारे योद्धाओं को समर्थन" में निहित है। राजनीतिक इच्छाशक्ति, वैज्ञानिक नवाचार और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के संयोजन से भारत सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करने और लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए तत्पर है।

जैसे-जैसे भारत वर्ष 2047 तक सिकल सेल रोग उन्मूलन के अपने लक्ष्य की ओर आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन इसमें आशा की किरण बनकर उभरा है। यह इस बात का द्योतक है कि जब सरकार, स्वास्थ्य सेवा पेशेवर और समुदाय समान हित के लिए एकजुट होते हैं, तो क्या कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी व्यक्ति को इस रोग के कारण होने वाले दर्द और पीड़ा को न सहना पड़े।

सिकल सेल एनीमिया के विरुद्ध भारत की लड़ाई सिर्फ एक आनुवंशिक रोग से लड़ने तक सीमित नहीं है। यह हाशिए पर रहने वाले हमारे देश के समूहों के लिए समानता, सम्मान और स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता है। मीना जैसी महिलाओं के अनुभवी मार्गदर्शन में, यह मिशन लक्षित स्वास्थ्य सेवा पहलों की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है, जो जनजातीय स्वास्थ्य चुनौतियों के समाधान में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

आइए, इस अभूतपूर्व प्रयास का जश्न मनाएं और एक स्वस्थ, अधिक समावेशी भारत के निर्माण के अपने संकल्प को दोहराएं।



सामाजिक और आर्थिक विकास पर भी गहरा असर डाला है, और यह बीमारी भौगोलिक अलगाव एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच के कारण और भी जटिल हो गई है। इस गंभीर आवश्यकता को पहचानते हुए, भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में जुलाई 2023 में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की

सिकल सेल रोग में लाल रक्त कोशिकाओं का आकार बदल जाता है, जिससे उनकी ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता कम हो जाती है और धीरे-धीरे गंभीर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं उत्पन्न होने लगती हैं। आदिवासी जनसंख्या के बीच इसका प्रभाव विशेष रूप से गहरा है, क्योंकि वे इस आनुवंशिक बीमारी से असमान रूप से प्रभावित होते हैं। ग्लोबल बर्डन

पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन में अग्रणी भूमिका निभा रहा हिमाचल प्रदेश

प्रदेश सरकार ने राज्य में ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक नई ईको-टूरिज्म नीति लागू की है, जिसके अंतर्गत राज्य के विभिन्न वन वृत्तों में 77 ईको-टूरिज्म स्थलों का विकास किया जा रहा है। प्रदेश सरकार की इस पहल से आगामी पांच वर्षों में 200 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। नई ईको-टूरिज्म नीति का उद्देश्य प्रकृति की रक्षा करते हुए पर्यटकों को आकर्षित करना, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को हरित व सतत् विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश सरकार हिमाचल को विश्व स्तर पर एक प्रमुख ईको-टूरिज्म गंतव्य के रूप में विकसित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

हिमाचल प्रदेश बर्फ से ढकी पहाड़ियों, घने जंगलों, निर्मल नदियों और समृद्ध जैव विविधता के कारण सदैव प्रकृति प्रेमियों के लिए पसंदीदा गंतव्य रहा है। अब राज्य सरकार इन प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए उनका समुचित दोहन कर रही है जिसके लिए ईको पर्यटन नीति-2024 तैयार की गई है। ईको-टूरिज्म का अर्थ है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना प्राकृतिक स्थलों की यात्रा करना। हिमाचल प्रदेश की ईको-टूरिज्म नीति-2024 विशेष रूप से इन्हीं नियमों पर आधारित है जिससे पर्यटन और प्रकृति दोनों का संरक्षण सुनिश्चित होगा।

इस नीति के तहत राज्य के विभिन्न भागों जैसे शिमला, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, रामपुर, सोलन, नाहन, हमीरपुर, नालागढ़, धर्मशाला, पालमपुर, चंबा, डलहौजी, नूपुर और रिकांगपिओ में 77 ईको-टूरिज्म स्थलों का विकास किया जा रहा है। इनमें से सात प्रमुख स्थलों-शिमला में पॉटर हिल और शोधी, कुल्लू में सोलंग नाला और पार्वती घाटी में कसोल-के लिए ईको-टूरिज्म ऑपरेटर्स का चयन पहले ही कर लिया

* प्रकृति के संरक्षण के साथ पर्यटन को मिल रहा बल

गया है तथा शेष स्थलों का विकास चरणबद्ध 188 तरीके से किया जा रहा है। पर्यटक यहां ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग, फॉरेस्ट कैपिंग, प्रकृति वॉक, होमस्टे और प्रकृति ट्रेल मार्ग जैसे पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों का आनंद ले सकेंगे।

हिमाचल प्रदेश अपनी समृद्ध जैव विविधता की रक्षा और संवर्धन में भी महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। वर्ष 2030 तक वनों की संख्या को 30 प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत महिला मंडल, युवा मंडल, स्वयं सहायता समूह और संयुक्त वन समितियां एक से पांच हेक्टेयर जंगल भूमि पर पांच वर्षों तक पौधारोपण और देखभाल करेंगी। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इस वर्ष, 1,000 से 1,500 हेक्टेयर जंगल भूमि में पौधारोपण किया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 20 करोड़ रुपये है। सरकार द्वारा पौधों की देखभाल के लिए प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त 1.2 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। ये प्रयास न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं बल्कि हरित और व्यवस्थित जंगल क्षेत्रों के निर्माण से पर्यावरण प्रेमियों को आकर्षित करके सतत पर्यटन को भी बढ़ावा देते हैं।

इस ईको-टूरिज्म गतिविधि का एक महत्वपूर्ण भाग स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित बनाना है। प्रत्येक वन वृत्त में ईको-टूरिज्म समितियां बनाई गई हैं, जो इन परियोजनाओं का संचालन कर रही हैं। स्थानीय युवाओं को नेचर गाइड और मल्टी-पर्पज वर्कर के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है तथा अब तक 70 से अधिक गाइड और 135 मल्टी-पर्पज वर्कर्स को हिमाचल प्रदेश ईको-टूरिज्म सोसाइटी द्वारा प्रशिक्षित किया जा चुका है। इससे लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है तथा प्रकृति की सुरक्षा के प्रति जागरूक भी हो रहे हैं।

पर्यटकों के लिए यात्रा और बुकिंग

की सुविधा को सरल बनाने के लिए सरकार ने ईको-टूरिज्म सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाई हैं। 100 से अधिक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस और कैपिंग साइट्स की बुकिंग अब हिमाचल प्रदेश ईको-टूरिज्म सोसाइटी की वेबसाइट के माध्यम से की जा सकती है तथा ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम भी शुरू किया गया है। 245 से अधिक ट्रैकिंग रूट्स को कठिनाई स्तर के आधार पर चिह्नित और सूचीबद्ध किया गया है तथा पर्यटकों के मार्गदर्शन के लिए एक मोबाइल ऐप भी तैयार किया जा रहा है।

नई ईको पर्यटन नीति में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और संशोधित वन संरक्षण अधिनियम वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, 2023 के राष्ट्रीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया है। शिमला, पालमपुर, कुल्लू, सिराज और मंडी जैसे वन मंडलों की कार्य योजनाओं में ईको-टूरिज्म अध्ययनों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है।

इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। वर्ष 2024 में हिमाचल प्रदेश में लगभग दो लाख पर्यटक आए, जिनमें 82 हजार विदेशी पर्यटक शामिल रहे। जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 13.24 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। चूंकि पर्यटन, प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 7.78 प्रतिशत का योगदान देता है तथा यह नई नीति राज्य की अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होगी।

वर्तमान सरकार ने अपने अटार्क वर्ष के कार्यकाल में ईको-टूरिज्म के क्षेत्र में मजबूत आधार तैयार किया है। पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर हिमाचल प्रदेश ने दिखा दिया है कि पर्यटन और प्रकृति साथ-साथ आगे बढ़ सकते हैं। यह ईको-टूरिज्म परियोजना राज्य के लिए एक हरित, स्वच्छ और आत्मनिर्भर भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है।

समृद्धि और आत्मनिर्भरता की राह पर अग्रसर हिमाचल प्रदेश

79वें स्वतंत्रता दिवस की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत की आजादी, एकता और अखंडता वर्षों के संघर्ष और वीर सपूतों के असंख्य बलिदानों का प्रतिफल है। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि देश की आन-बान और शान बनाए रखने के लिए हमारे प्रदेश के वीर जवानों ने हमेशा प्रमुख भूमिका निभाई है तथा अपने कर्तव्य को निभाते हुए बलिदान और शौर्य की अमर गाथाएं लिखी हैं। यह गर्व की बात है कि हिमाचल के वीर सपूतों ने 4 परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 11 महावीर चक्र और 23 कीर्ति चक्र जीते हैं। देश का पहला परमवीर चक्र, प्रदेश के वीर सपूत मेजर सोमनाथ शर्मा को प्राप्त हुआ था। इसके बाद, कर्नल डी.एस. थापा, कैप्टन विक्रम बतरा, तथा सूबेदार मेजर संजय कुमार को भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

वर्ष 2023 में गंभीर प्राकृतिक आपदा का सामना हमने अपने संसाधनों से सफलतापूर्वक किया। इस साल भी मूसलाधार बारिश और बादल फटने के कारण आई विनाशकारी बाढ़ से हमें जान-माल का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इस आपदा से मंडी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। हमने 200 से अधिक बहुमूल्य जीवन खोए हैं और अधोसंरचना को लगभग दो हजार करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचा है। यह आपदा बहुत बड़ी है और प्रदेश सरकार संकट की इस घड़ी में प्रभावितों के साथ कंधों से कंधा मिलाकर खड़ी है। हमने आपदा के फौरन बाद युद्धस्तर पर राहत और पुनर्वास के कार्य शुरू किए तथा वर्ष 2023 की तरह इस बार भी आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है, जिसे 25 गुना तक बढ़ाया गया है।

इस पैकेज के अंतर्गत पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए दी जाने वाली 1 लाख 30 हजार रुपये की सहायता राशि को बढ़ाकर 7 लाख रुपये और आंशिक क्षति पर 12 हजार 500 रुपये की राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है। इसके अलावा क्षतिग्रस्त दुकान अथवा ढाबे, गौशाला, पशुओं की हानि, क्षतिग्रस्त पॉलीहाउस, कृषि व बागवानी भूमि के नुकसान आदि के लिए भी राहत एवं मुआवजा राशि में कई गुणा वृद्धि की गई है।

हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल में राजनीतिक, आर्थिक और प्राकृतिक आपदा जैसी गम्भीर चुनौतियों का मजबूती से सामना किया है। प्रदेश को समृद्धि और आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से आगे ले जाने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने हमारी सरकार पर भरपूर भरोसा किया। प्रदेशवासियों के समर्थन से हमने धनबल पर जनबल की जीत सुनिश्चित हुई है, जिससे लोकतंत्र सशक्त हुआ है।

हिमाचल के विकास और खुशहाली के लिए हमारी सरकार ने ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जिसने प्राकृतिक रूप से उगाई गई फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया है। मक्की पर 40 रुपये प्रति किलो का समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। अब तक 1,509 किसानों से लगभग 399 मीट्रिक टन मक्की समर्थन मूल्य पर खरीदी जा चुकी है और उनके बैंक खातों में 1.40 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। इसी प्रकार, गेहूं की खरीद भी 60 रुपये प्रति किलो की दर से की जा रही है और अब तक 838 किसानों से

2,123 क्विंटल गेहूं की खरीद की जा चुकी है। उनके खातों में 1.27 करोड़ रुपये जमा करवाए गए हैं। गेहूं के लिए परिवहन भाड़े पर सरकार ने 4.15 लाख रुपये की सब्सिडी दी है।

हमने प्राकृतिक विधि से उगाई गई कच्ची हल्दी के लिए 90 रुपये प्रति किलो का समर्थन मूल्य घोषित किया है। किसानों से 127 मीट्रिक टन कच्ची हल्दी खरीदी गई है और उनके खातों में 1.14 करोड़ रुपये जमा कर दिए गए हैं।

प्रदेश सरकार ने चम्बा जिले के पांगी उप-मंडल को प्रदेश का प्राकृतिक कृषि डिविजन घोषित किया है और घाटी के किसानों से अगले महीने से 60 रुपये प्रति किलो की दर से जौ की खरीद शुरू की जाएगी।

हमारी सरकार ने हमीरपुर जिले में स्पाइस पार्क और ऊना जिले में आलू प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने का फैसला लिया है। प्रदेश सरकार किसानों के हित में कृषि ऋण ब्याज योजना भी लेकर आई है।

हमने दूध उत्पादन के क्षेत्र में भी बहुमूल्य सुधार किए हैं। हिमाचल देश का पहला राज्य है जो दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान कर रहा है। वर्तमान में लगभग 38,400 किसानों से प्रतिदिन औसतन 2.25 लाख लीटर गाय का दूध 51 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है। इसी प्रकार, 1,482 भैंस पालकों से प्रतिदिन 7,800 लीटर दूध 61 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है। दुग्धा सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने के लिए दूध पर परिवहन सब्सिडी डेढ़ रुपये से बढ़ाकर 3 रुपये प्रति लीटर की गई है।

कांगड़ा जिले के ढगवार में 201 करोड़ रुपये की लागत से डेढ़ से तीन लाख लीटर प्रतिदिन तक की क्षमता वाला अत्याधुनिक दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जिससे चार जिलों के 35 हजार से अधिक दूध उत्पादकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी दूध प्रसंस्करण संयंत्र का विस्तार और निर्माण कार्य जारी है। पशुपालकों से 300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से जैविक खाद और वर्मी कम्पोस्ट खरीदने का कार्य शुरू कर हमने एक और चुनावी वादा पूरा किया है।

बागवानों के हित में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। यूनिवर्सल कार्टन का उपयोग अनिवार्य बनाने की ऐतिहासिक पहल से राज्य के बागवानों को अपनी फसल के बेहतर दाम मिल रहे हैं। वर्ष 2025 के लिए सेब, बी और सी ग्रेड के किन्नु, माल्टा और संतरे और सीडलिंग, कलमी व कच्चे अचारी आम पर 12 रुपये प्रति किलो का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, गलगल को 10 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा जाएगा।

वन प्रबंधन और वन क्षेत्र विस्तार में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपये लागत की राजीव गांधी वन संवर्द्धन योजना लागू की जा रही है।

पिछले अठ्ठाई वर्षों में हमने शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण-2025 में प्रदेश 5वें स्थान पर पहुंचा है जबकि 2021 में हमारी रैंकिंग 21वें पायदान पर फिसल गई थी। वार्षिक शिक्षा स्थिति-2025 रिपोर्ट में विद्यार्थियों के पढ़ने और सीखने के स्तर में हिमाचल ने 21वें स्थान से पहले स्थान पर छलांग लगाई है।

पूर्व सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए चुनावी वर्ष के आखिरी नौ

महीनों में बिना बजट और बुनियादी अधोसंरचना के 900 से ज्यादा शिक्षण व स्वास्थ्य संस्थान खोले। वर्तमान सरकार ने एक हजार से अधिक स्कूलों का युक्तिकरण कर स्कूलों के क्लस्टर बनाए हैं। इससे जहां गैर-जरूरी खर्चों में कटौती हुई है, वहीं पर्याप्त अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित होने से छात्रों को बेहतर शिक्षा भी मिल रही है।

विद्यार्थियों के शिक्षा स्तर में सुधार के लिए सभी सरकर स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम शुरू कर दिया गया है। प्रदेश के 6,297 प्राइमरी स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षाएं आरम्भ की जा चुकी हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधाओं वाला राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल चरणबद्ध तरीके से खोलने का कार्य प्रगति पर है।

हमने डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना शुरू कर पात्र विद्यार्थियों को देश-विदेश में शिक्षा के लिए 1 प्रतिशत ब्याज पर 20 लाख रुपये तक के ऋण का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत 32,000 बच्चों को मुक्त शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जा रही है।

पहली से आठवीं कक्षा के 5.35 लाख बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की पहल की गई है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार अध्यापकों को विदेश में एकसोजर विजिट और विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर भेजा गया है। छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तार कर दो वर्षों में 87,000 से अधिक विद्यार्थियों को 92 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

हमारी सरकार ने वर्ष 2026 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। ई-वाहनों को व्यापक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वाहन चालकों की सुविधा के लिए प्रदेश में छः ग्रीन कॉरिडोर स्थापित किए गए हैं। 124 करोड़ रुपये से बस अड्डों पर ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का कार्य जारी है। 327 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं।

हमारी सरकार ने युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना शुरू की है जिसके पहले चरण में ई-टैक्सी खरीदने के लिए 50 प्रतिशत उपदान का प्रावधान है। दूसरे चरण में निजी भूमि पर 100 से 500 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाने के लिए 50 प्रतिशत उपदान दिया जा रहा है। तीसरे चरण में किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जा रहा है।

ऊना जिला के पेखूबेला में 32 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना मात्र चार महीनों में जनता को समर्पित की गई है। इस परियोजना से सालाना 19 करोड़ 17 लाख रुपये के राजस्व लाभ का अनुमान है। प्रदेश सरकार ने ऊना, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर, मंडी और शिमला जिलों में 501 मेगावाट की क्षमता वाले 5 सौर पार्क और 212 मेगावाट की क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का भी निर्णय लिया है।

महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान देने के लिए हमने 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना शुरू कर 1500 रुपये मासिक सम्मान राशि देना आरंभ किया है। महिला कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली आर्थिक सहायता कई गुण बढ़ाई गई है।

प्रदेशवासियों को विश्व स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के

लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि किसी को भी इलाज के लिए हिमाचल से बाहर जाने की ज़रूरत पड़े। एक ऐतिहासिक पहल के तहत रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत शिमला स्थित अटल इंस्टीट्यूट ऑफ सूपर स्पेशलिटीज़ से की गई है।

कैंसर मरीजों के लिए मुक्त इलाज और दवाइयों का प्रावधान किया गया है। हमीरपुर में उत्कृष्ट कैंसर अस्पताल स्थापित किया जा रहा है। आईजीएमसी शिमला में नए कैंसर अस्पताल भवन और ट्रॉमा सेंटर की सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। आईजीएमसी शिमला और टांडा मेकिल कॉलेजों में पैट स्कैन मशीन की सुविधा भी शुरू की गई है।

हिमकेयर योजना के लाभार्थियों को बेहतर इलाज देने की सुविधा के लिए इसका विस्तार किया गया है। अब आपात स्थिति में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और अधीक्षक भी हिमकेयर कार्ड बना सकेंगे। बीपीएल, मनरेगा, फेरीवालों, अनाथ और जेल बंदियों के निःशुल्क हिमकेयर कार्ड बनाने का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार किया जा रहा है और प्रदेश के 16 स्थानों पर हेलीपोर्ट विकसित किए जा रहे हैं। प्रमुख धार्मिक स्थलों को रोप-वे से जोड़ा जा रहा है। कांगड़ा जिला को प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनाया जा रहा है। देहरा उप-मण्डल के बनखंडी में 619 करोड़ रुपये से वन्य प्राणी उद्यान स्थापित किया जा रहा है।

प्रदेश सरकार दूरस्थ क्षेत्रों तक सड़क सुविधा पहुंचाने की प्राथमिकता दे रही है। दो वर्षों की अवधि में 1,584 किलोमीटर लम्बी सड़कों और 143 पुलों का निर्माण किया गया है। आजादी के बाद पहली बार शिमला जिले के दूर-दराज क्षेत्र डोडरा-क्वार की सड़क को पक्का किया जा रहा है। इसी तरह, बड़ा भंगाल को भी सड़क सुविधा से जोड़ा जा रहा है।

प्रदेशवासियों को 24 घंटे पेयजल सुविधा सुनिश्चित करने तथा पानी की गुणवत्ता सुधारने के दृष्टिगत ठोस कदम उठाए गए हैं। साफ और कीटाणु रहित पेयजल प्रदान करने के लिए 69 टेस्टिंग लैब स्थापित की गई हैं।

हमने करूणामूलक रोजगार नीति में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की है। अब प्रति परिवार वार्षिक आय पात्रता मापदंड को 2 लाख 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया गया है।

हमारी सरकार ने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अनूठी पहल की है जिसके तहत मैं खुद और मेरे मंत्रीमण्डल के सहयोगी दूर-दराज क्षेत्रों में लोगों से मिलते हैं व उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करते हैं।

वित्तीय संसाधन जुटाने और फिजूलखर्ची रोकने के प्रयासों के तहत हमने आबकारी नीति में बदलाव, शराब के ठेकों की नीलामी व निविदाओं, दूध उपकर, विभिन्न विभागों में भी स्टाफ के युक्तिकरण, लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं की टेंडर प्रक्रिया में बदलाव जैसे ठोस कदमों के माध्यम से अठ्ठाई वर्षों में हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया है। वित्तीय प्रबंधन की दिशा में प्रदेश सरकार ने ग्रीन बजट की शुरुआत कर एक नई पहल की है।

इतना ही नहीं, हमने केंद्र सरकार के समक्ष भी हिमाचल के हितों की मजबूती से पैरवी की है।

-सुखविंद सिंह सुखर्व
मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश

नीति आयोग से ग्रीन बोनस की मांग, राजस्व घाटा अनुदान में वृद्धि, हिमाचल की ऋण सीमा को दो प्रतिशत बढ़ाने, 110 मेगावाट शानन विद्युत परियोजना का अधिग्रहण पंजाब से वापिस लेने, भाखड़ा बांध प्रबंधन बोर्ड से बिजली एरियर जारी करने और फोर-लेन सड़क परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाने के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं।

हमारी सरकार संवेदनशील वर्गों का संरक्षण और कल्याण सुनिश्चित कर रही है। हिमाचल अनाथ व बेसहारा बच्चों और महिलाओं के लिए कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना में 6,000 बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया गया है। इन बच्चों की पढ़ाई, जेब खर्च का जिम्मा प्रदेश सरकार उठा रही है।

कांग्रेस के चुनावी घोषणा-पत्र की 6 गारंटियां पूरी की गई हैं। कांग्रेस सरकार ने अपना वादा पूरा करते हुए 1.36 लाख एनपीएस कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की है।

आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल में 74,600 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। इसमें सरकारी क्षेत्र में लगभग 23,200 और निजी क्षेत्र में 51,400 से अधिक रोजगार के अवसर शामिल हैं।

प्रदेशभर में, विशेषकर युवाओं में, नशे की बढ़ती लत चिन्ता का विषय है। इस सामाजिक बुराई के कारण हमने कई बहुमूल्य जीवन खोए हैं। हमारी सरकार ने नशे के आदि व्यक्तियों के उपचार, पुनर्वास और नशे सहित संगठित अपराधा को रोकने के लिए विधेयक पारित किए हैं, जिनमें नशा तस्करों को मृत्युदंड, आजीवन कारावास, 10 लाख तक जुर्माना, संपत्ति जब्त करने का प्रावधान, उनके पुनर्वास एवं आजीविका सहायता सहित विभिन्न प्रावधान शामिल हैं।

हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा पीआईटी एनडीपीएस एक्ट को कड़ाई से लागू किया गया है। इसके तहत 42 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की गई है और 70 तस्करों की संपत्ति चिन्हित कर अब तक 44 तस्करों को हिरासत में लिया गया है। जिला सिरमौर के कोटला बड़ोग में 100 बिस्तर क्षमता का उत्कृष्ट नशा-मुक्ति केंद्र स्थापित किया जा रहा है।

प्रदेश सरकार पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें मिलने वाली अनुग्रह राशि को बढ़ाया गया है। हमने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि में भी वृद्धि की है।

मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हिमाचल को देश का सबसे समृद्ध तथा आत्मनिर्भर राज्य बनाने के हमारे संकल्प में वित्तीय संकट कोई बाधा नहीं बनेगा। हम आपकी उम्मीदों के अनुसार और आपके सहयोग से अपने इस सुंदर पहाड़ी राज्य को विकास के नए आयाम देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

अंत में, मैं एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं तथा समस्त प्रदेशवासियों के सुखमय और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।

जय हिन्द, जय हिमाचल...



79^{वें} स्वतंत्रता दिवस की हिमाचलवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

“स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों को स्मरण करने का अवसर है। देश की आन-बान और शान की स्थातिर अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आइए, प्रदेश की उन्नति व खुशहाली के लिए एकजुट प्रयास का संकल्प लें।”

- सुखविन्द्र सिंह सुक्खू

क्रांतिकारी पहल

MSP देने वाला पहला राज्य:

- प्राकृतिक रूप से उगाए गोहूँ पर ₹60, मक्की पर ₹40, गाय के दूध पर ₹51 और भैंस के दूध पर ₹61 MSP देने का ऐतिहासिक निर्णय

शिक्षा में श्रेष्ठ प्रदर्शन:

- राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में हिमाचल 21^{वें} रैंक से 5^{वें} तथा पढ़ने व सीखने के स्तर में पहले रैंक पर पहुंचा

मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना :

- अनाथ बच्चों को 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' का दर्जा देकर उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, जेब खर्च आदि के लिए कानून बनाने वाला पहला राज्य

स्वास्थ्य सेवा में मील पत्थर:

- AIMSS चमियाना (शिमला) में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत, अत्याधुनिक तकनीक से विश्वस्तरीय इलाज की सुविधा उपलब्ध

नियमों में बदलाव कर आपदा प्रभावित परिवारों को दिया ऐतिहासिक मुआवजा

आपदा प्रभावितों के लिए राहत	पहले थे	अब दिए
क्षतिग्रस्त घरों का पुनः निर्माण	₹1.30 लाख	₹7 लाख
कच्चे घरों को आंशिक नुकसान	₹4,000	₹1 लाख
पक्के घरों को आंशिक नुकसान	₹6,500	₹1 लाख
दुकान/ढाबे को नुकसान	₹25,000	₹1 लाख
गौशाला को नुकसान	₹3,000	₹50,000
कृषि/बागवानी भूमि की क्षति	₹3,615	₹10,000 प्रति बीघा
गाय/भैंस की मृत्यु	₹37,500	₹55,000



सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश

अपनी नाकामियां स्वीकारे सरकार: जयराम ठाकुर

शिमला/शैल। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जारी ब्यान में कहा कि उन्होंने विधानसभा में नियम 67 के तहत आपदा पर चर्चा की मांग की जिसे सरकार द्वारा विपक्ष के दबाव में स्वीकार करना पड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों द्वारा भेजी गई आपदा राहत सामग्री को भी अपना बनाने की कोशिश की। हमारी पार्टी द्वारा और प्रदेश के लोग जो राहत सामग्री ला रहे थे सरकार द्वारा संरक्षित अधिकारियों ने नाका लगवाकर राहत सामग्री एसडीएम और तहसीलदार को देने के लिए दबाव बनाया। सरकार अगर खुद कुछ नहीं कर सकती तो जो लोग कर रहे हैं, उन्हें करने दिया जाये। जो राशन सरकार द्वारा हेलीकॉप्टर से भेजा गया वह मुख्यमंत्री के चहेते कांग्रेसी नेता के घर गया। उन्होंने साथ ही कहा कि सरकार मुकद्दमा करके न हमें डरा सकती है न दबा सकती है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा में सरकार द्वारा जिस तरीके का रवैया अपनाया गया है वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार जब कहती है कि हजार करोड़ का नुकसान हुआ है लेकिन राहत के और सड़कों की बहाली के लिए मुख्यमंत्री द्वारा दो करोड़ रुपये की सहायता कई किस्तों में दी गई। इसके बाद भी सरकार चाहती है कि हम उनकी वाहवाही करें। लेकिन सरकार एक बार इस बात का मूल्यांकन करें कि उन्होंने जो किया है क्या वह सही है? सरकार द्वारा पहुंचाई गई राहत पर्याप्त है? डेढ़ महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी अगर सड़कें नहीं खुली हैं तो यह काम किसका था?

उन्होंने कहा कि 20 से ज्यादा जेसीबी मशीनें लगाकर हमने रास्ते खोले। और सरकार कुछ मशीनें लगा कर संख्या बताती है कि हमने इतनी मशीनें लगाई हैं। सवाल यह नहीं है कि सरकार द्वारा कितनी मशीनें लगाई गई हैं? सवाल यह है कि कितनी मशीनें लगाई जानी चाहिए थी जिससे कि समय फिर रास्ता खुल जाये? अब सरकार को करना क्या चाहिए था उस पर बात की जानी चाहिए? जिस तरीके से लोगों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे हो इस पर बात की जानी चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि

सत्ता के संरक्षित नेताओं ने आपदा को एक अवसर बनाया और भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ गये। जो रास्ते हमने लोगों से मशीनें मांग कर खोले हैं आज कांग्रेस के नेता कहते हैं कि उन सड़कों का



काम निकालो और टेंडर हमारे नाम पर बना कर उसका पैसा हमें दे दो। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में इस दर्जे का भ्रष्टाचार और नीचे दर्जे का कार्य हो रहा है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कैसे पहुंचाई जाये इसकी वजह सरकार वहां जो कुछ है उसे कैसे छीन जाये इस पर ही

सारा ध्यान लगा कर रखा था।

जयराम ठाकुर ने कहा कि ढाई साल से ज्यादा समय से सरकार हॉर्टिकल्चर कॉलेज छीनना चाहती थी और आपदा के नाम पर वह काम सरकार ने किया। फौरी राहत

के 2500 रुपये देने में सरकार को हफ्तों लग गये। लेकिन 62 लोगों के खिलाफ मुकद्दमा करने में 1 मिनट भी नहीं लगा। इस तरीके में सरकार आपदा प्रभावितों के जख्मों पर मरहम लगाना चाहती है। सरकार की आंखों में पूर्व सरकार द्वारा बनवाये गये संस्थान

और स्ट्रक्चर चुभ रहे हैं। इसलिए बार-बार उनका वह गलत तरीके से हवाला देती है। अगर सरकार को यह चीजें इतनी खल रही है तो वह बुलडोजर लेकर जाये और गिरा दे।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आपदा प्रभावितों के लिए सरकार अस्थाई शेल्टर बनाये। जहां पर आपदा प्रभावितों को अस्थाई तौर पर बसाया जा सके। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं न जिनके पास घर है न घर बनाने के लिये जमीनें। इस आपदा के दौरान बहुत से अधिकारियों ने अच्छा काम किया है। उसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन कुछ अधिकारियों ने और क्या-क्या किया है यह बात मुख्यमंत्री को पता होनी चाहिए। बहुत जगहों पर बहुत सुधार की जरूरत है। सरकार को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं की

खींचतान हर जगह इतनी ज्यादा है जिसकी कोई बात नहीं। यह इसलिये हो रहा है क्योंकि पार्टी में खींचतान है। सरकार में खींचतान है। इसका खामियाजा आपदा प्रभावितों को उठाना पड़ रहा है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि स्थगन प्रस्ताव लाकर आपदा पर चर्चा की मांग पर की संसदीय कार्य मंत्री द्वारा कहे गये शब्द ठीक नहीं है। आसमान तो सारे प्रदेश में दर्जनों जगह फट चुका है। सैकड़ों लोगों की जान भी इसमें जा चुकी है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। हजारों की संख्या में पशु मारे गए। हजारों बीघा जिन बह गई। हजारों बीघा बाग बह गए। क्या सरकार के लिए यह बड़ा विषय नहीं है। इसलिए सरकार चर्चा से भाग कर आपदा प्रभावितों के साथ अन्याय कर रही है। चर्चा से ही राहत बचाव पुनर्वास और पुनर्निर्माण के बेहतर रास्ते निकलेगें।

विधानसभा सत्र के कटघरे में उतारेगा विपक्ष: रणधीर शर्मा

शिमला/शैल। भाजपा विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा की गई। विधायक दल की बैठक में सुखराम चौधरी,



विपिन परमार, बिक्रम ठाकुर, रणधीर शर्मा, अनिल शर्मा, विनोद कुमार, इंदर सिंह गांधी, राकेश जमवाल, त्रिलोक जमवाल, डी एस ठाकुर, आशीष शर्मा, डॉ. जनक राज, लोकेंद्र कुमार, रीना कश्यप, दीप राज, दिलीप ठाकुर, इंदर दत्त लखनपाल, जीत राम कटवाल, हंस राज, ने भाग लिया।

विधायक रणधीर शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस पार्टी की सरकार को विपक्ष द्वारा कटघरे में उतारा जायेगा। जिस प्रकार

से सत्ताधारी दल ने प्रदेश की जनता से अन्याय किया, कर्मचारियों की किसी भी मांग को नहीं माना, पूरे प्रदेश में या तो संस्थाओं को बंद किया और चले चलाएं संस्थाओं को

स्थानांतरण कर दिया, आपदा के दौरान सरकार का एक बहुत बड़ा नकारात्मक रुख रहा, पूरे प्रदेश में झूठी एफआईआर दर्ज की गई, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के विधायकों एवं आपदा प्रभावितों पर भी झूठी मुकद्दमे दर्ज किए गए। इस प्रकार के अनेकों मुद्दे हैं जिस पर वर्तमान सरकार को विधानसभा सत्र में घेरा जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता का विश्वास सरकार से उठ गया है, कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में अव्यवस्थित हो रही है, दिनदहाड़े

अपहरण के मामले पूरे प्रदेश में सामने आ रहे हैं, नशे का व्यापार बढ़ रहा है, खनन शराब डब्बा माफिया प्रदेश में जोरदार गति पकड़ रहा है, पर सरकार चुप बैठी है और कुछ नहीं कर रही।

उन्होंने कहा कि सरकार की वित्तीय हालत बिगड़ रही है, भ्रष्टाचार फल फूल रहा है, यहां तक की आपदा के समय भी भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। आपदा के समय कितनी राशि प्रदेश सरकार ने खर्ची उसका विवरण अभी तक जनता के समक्ष

नहीं आया है, जहां केंद्र सरकार ने 7000 करोड़ से अधिक की राशि हिमाचल प्रदेश की सरकार को आपदा प्रबंधन के लिए भेजी है उसके विपरीत सरकार ने जनता को राहत नहीं पहुंचाई है।

रेल और हवाई अड्डों की विस्तार पर भी काम अच्छे से नहीं चल रहा है और इसके साथ-साथ वर्तमान सरकार ने केंद्र विश्वविद्यालय से भी अभी तक न्याय नहीं किया है। भाजपा विधायक दल सरकार के मुख्यमंत्री एवं सरकार के मंत्रियों से हर मुद्दे पर जवाब मांगेगा।

रेल परियोजनाओं के

.....पृष्ठ 1 का शेष

से भिन्न हैं और यहां के आय संसाधन भी सीमित हैं। इसलिए केंद्र सरकार को अपने नैतिक दायित्व का वहन करते हुए प्रदेश में निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं की लागत स्वयं वहन करनी चाहिए।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि वह स्वयं इन परियोजनाओं की समय-समय पर समीक्षा करते हैं और रेल मंत्रालय के साथ समन्वय बनाए रखते हैं ताकि कार्य में अनावश्यक देरी न हो। उन्होंने विपक्ष

से आग्रह किया कि वे तथ्यों की पुष्टि के बिना ब्यानबाजी करने से बचें और प्रदेश के हित में मिलकर प्रयास करें।

उन्होंने दोहराया कि हिमाचल प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के साथ साझेदारी में रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है, ताकि प्रदेश के नागरिकों को बेहतर यातायात सुविधा, तेज़ कनेक्टिविटी और नए आर्थिक अवसर प्राप्त हो सकें।